



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 16, 2005/अग्रहायण 25, 1927

No. 319]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 16, 2005/AGRAHAYANA 25, 1927

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

विषय : परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन 1 जनवरी, 2006 से बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (1).—दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था।

2. सरकार ने परिधान एवं निटवियर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 1 जनवरी, 2006 से एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कैसर शमीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

Subject : Extension of the operation of residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2006.

No. 1/61/2004-Exports-I (1).—Attention is invited to Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, vide which the Government decided to enforce operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies initially for one year with effect from 1st January, 2005.

2. Now, the Government has decided to extend the operation of the residuary provisions of Garments and Knitwears Export Entitlement (Quota) Policies for a further period of one year with effect from 1st January, 2006.

3. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

KAISER SHAMIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

विषय : यार्न, फैब्रिक एवं मेडअप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन 1 जनवरी, 2006 से बढ़ाया जाना।

सं. 1/61/2004-निर्यात-I (2).—दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 1/61/2004-निर्यात-I की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा सरकार ने यार्न, फैब्रिक एवं मेडअप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन आरंभिक तौर पर 1 जनवरी, 2005 से एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया था।

2. सरकार ने यार्न, फैब्रिक एवं मेडअप्स निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के अवशिष्ट प्रावधानों का प्रचालन अब 1 जनवरी, 2006 से एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

कैसर शमीम, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2005

Subject : **Extension of the operation of residuary provisions of Yarn, Fabrics and Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies with effect from 1st January, 2006.**

No. 1/61/2004-Exports-I (2).—Attention is invited to Notification No. 1/61/2004-Exports-I dated 9th November, 2004, *vide* which the Government decided to enforce operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics and Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies initially for one year with effect from 1st January, 2005.

2. Now, the Government has decided to extend the operation of the residuary provisions of Yarn, Fabrics and Made-ups Export Entitlement (Quota) Policies for a further period of one year with effect from 1st January, 2006.

3. All other terms and conditions of the Notification mentioned in Para 1 above will remain unchanged.

KAISER SHAMIM, Jt. Secy.